राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-47 ■ अंक-02 ■ मई 2025 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-36

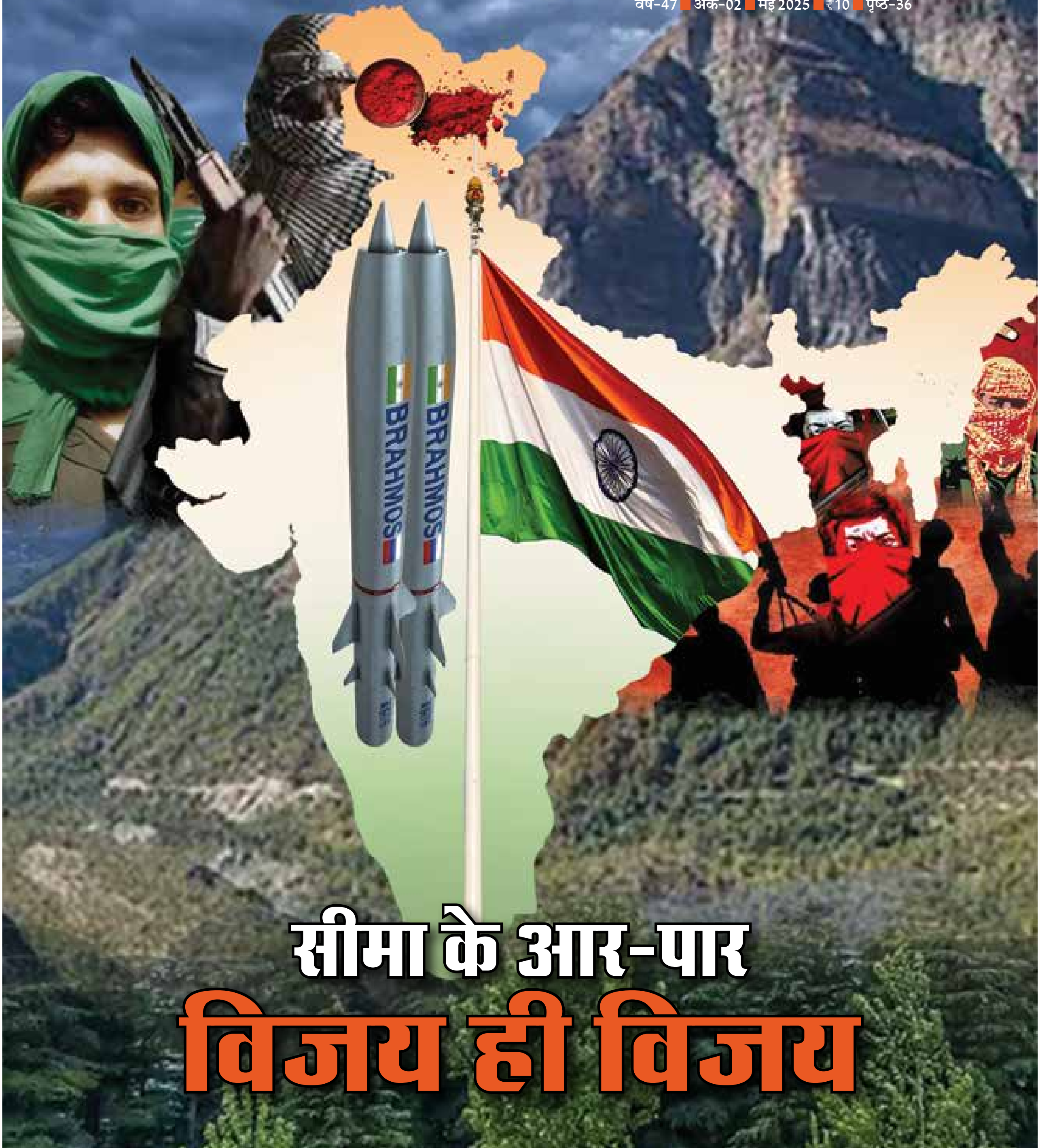

सीमा के आर-पार
विजय ही विजय

छात्र संसद

नई दिल्ली : जनजातीय छात्र संसद का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके एवं अभाविप पदाधिकारी

नई दिल्ली : छात्रा संसद का शुभारंभ करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं अभाविप पदाधिकारी

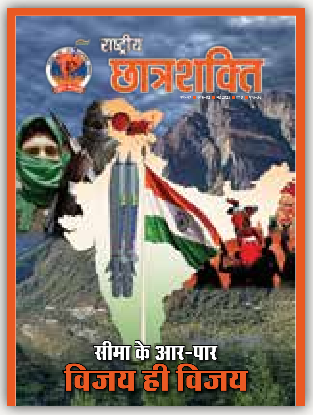

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष–47, अंक–02
मई 2025

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.x.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05

OPERATION SINDOOR
INDIA'S 'TRINETRA' OF DEFENCE, DIPLOMACY AND DECISION-MAKING

Operation Sindoor, India's assertive response to the Pahalgam massacre, involved coordinated strikes deep inside Pakistan, targeting terrorist infrastructure.

संपादकीय	4
माओवाद : अंत की ओर	9
सुशासन से पस्त बंदूक का शासन	14
जेएनयू में संयुक्त सचिव सहित 24 काउंसलर पदों पर अभाविप की जीत	18
बराक संस्कृति को दर्शाने वाली भव्य शोभायात्रा का आयोजन	19
Upholding the Honor of Our Nation : A Constitutional and Legal Perspective	20
छात्र संसद : मुद्दों पर मंथन, समाधान की चर्चा	23
ज्ञान, शील एवं एकता से होगा राष्ट्र का पुनर्निर्माण : डा. मोहन भागवत	26
भारत की स्वतंत्रता सेनानी रानी अबक्का	28
DIPEX-2025 : Showcases Innovation and Youth Talent Across Maharashtra and Goa	31
प्राध्यापक कार्यकर्ता वर्ग का आयोजन	33
श्रीमद्भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र 'विश्व स्मृति रजिस्टर' में शामिल	34
लेह में बना विश्व का पहला 3डी-प्रिंटेड बंकर	34

वैधानिक सूचना : 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

भारत किस जटिल परिस्थिति से गुजर रहा है, इसका अनुभव संभवतः पहली बार पूरी तीव्रता के साथ जन सामान्य के सामने आया। गत एक माह के अंदर लोगों ने देश को सीमा के भीतर और बाहर, दोनों मोर्चों पर लड़ते देखा।

एक ओर देश माओवाद के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर सीमा पार से प्रेरित आतंकवादियों ने पहलगांव के निकट बैसरन घाटी में निहत्थे पर्यटकों पर बर्बर हमला करके 27 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इन उन्मादियों ने लोगों का धर्म पूछ कर उनकी नृशंस हत्या की और 'मोदी को बता देना' कह कर भारत के सत्ता प्रतिष्ठान को सीधी चुनौती दी।

कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर जिस समय आईईडी के विस्फोट हो रहे थे, उसी समय कश्मीर से लेकर गुजरात तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान, अपने सहयोगी देशों से भीख में मिले ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा था। एक ओर आतंक के बल पर भारत को झुकाने के राक्षसी मंसूबे थे, तो दूसरी ओर आतंक के समूल नाश का दैवी संकल्प। इस संकल्पों को पूरा करने के लिए हर देशभक्त अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए सन्नद्ध था। किन्तु इस परिस्थिति में भी एक समूह था, जो मानवाधिकारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था तो दूसरा समूह वह भी था, जो बार-बार इस बात को दुहरा रहा था कि अगर पहलगांव के अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों का प्रयोग कर सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। दोनों ही समूहों में मुट्ठी भर लोग ही हैं, किन्तु उन्हें महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले शहरी (अर्बन) नक्सल और विदेशों में मौजूद उनके नेटवर्क का भरपूर सहयोग मिलता है। मीडिया और सोशल मीडिया में गहरी पैठ बना चुका उनका विस्तृत गठजोड़ अनेक बार तो इंटरनेट की दुनिया में हावी होता दिखाई पड़ता है।

एक ओर आतंक के बल पर भारत को झुकाने के राक्षसी मंसूबे थे, तो दूसरी ओर आतंक के समूल नाश का दैवी संकल्प। इस संकल्पों को पूरा करने के लिए हर देशभक्त अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए सन्नद्ध था।

इन सारी चुनौतियों के एक साथ घिर आने के बाद भी भारत उन्हें चीर कर एक विजेता के रूप में उभर कर आया, जिसका लोहा दुनिया भी मान रही है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए गत एक दशक में निरंतर प्रयासों की एक श्रृंखला है, जिसके परिणामस्वरूप यह सुफल प्राप्त हुआ है। सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के निर्माण का संकल्प लेकर हजारों-लाखों मौन तपस्वी साधकों ने अपना जीवन खपाया है, तब कहीं आत्मविश्वास का यह प्रकटीकरण हो सका है।

अभाविप भी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस अभियान में सहयात्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाती रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिषद के नए कार्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मा. मोहन भागवत का पाथेय प्राप्त हुआ। नवीन भवन परिषद कार्य को गति प्रदान करने तथा लक्ष्यपूर्ति के लिए नए क्षितिज का स्पर्श करने में उपकरण बनेगा, यह विश्वास है।

आपका
संपादक

India's 'Trinetra' of Defence, Diplomacy and Decision-Making

Dr. Abhishek Srivastava

Operation Sindoor, India's assertive response to the Pahalgam massacre, involved coordinated strikes deep inside Pakistan, targeting terrorist infrastructure. Unlike previous actions, it aimed to inflict material costs, degrading terrorist capabilities and challenging Pakistan's military-terrorist nexus. This operation signifies a shift in India's strategic thinking towards routine, calibrated retaliation, signalling a new normal where military responses against terrorism are prioritised.

On 22nd April, the terrorist attack in Pahalgam that resulted in the death of 26 innocent lives led to intense debate on the involvement of Pakistan as a state sponsor of terrorism and the action that India as a country needed to take. Having carried out surgical strikes in the past by special forces in 2016, post the Uri terror attack and by the Indian Air Force in 2019, post

the Pulwama terror attack; the expectation from the domestic constituency had only increased. While diplomatic steps taken by the government included holding the Indus Water Treaty in abeyance, expulsion of military advisors, closing of the border and revoking visas of Pakistan nationals immediately; these would take time to fructify and take effect.

Operation Sindoor, launched on May 7, 2025, in response to the Pahalgam terror attack, represents a transformative moment in India's national security strategy. Combining military precision, diplomatic coordination, and strategic messaging, the operation redefined India's approach to counterterrorism, escalation control, and deterrence. It was a significant demonstration of India's military and strategic power, executed through a combination of military and non-military means. This multi-dimensional operation effectively neutralised terrorist threats, deterred Pakistani aggression, and firmly enforced India's zero-tolerance policy towards terrorism.

In a deliberate and carefully planned attack that was focused, measured and non-escalatory, the Indian Armed Forces struck nine terrorist training camps, indoctrination centres and staging areas inside Pakistan and Pakistan Occupied Jammu & Kashmir. These were targeted based on credible intelligence; ensuring no loss to civilian lives and property and no military targets were struck. Pakistan indeed was taken by surprise and has since then reacted with drone and missile attacks, targeting Indian cities, some religious places and small villages.

From Uri to Balakot to Sindoor

Over the past decade, India has progressively transformed its response to Pakistan's sponsored terrorism. Its actions have grown in scale, using new technologies, triggering larger cycles of violence, and seeking more expansive effects.

For years, despite grave provocations such as the 2001 attack on the Indian parliament, the 26/11 attack in Mumbai, and even multiple smaller attacks during the UPA's government, India's response was inept and unsatisfactory. That pattern of inaction began to change in 2016, when in response to an attack at Uri, Indian special forces attacked the terrorist camps across the Line of Control. At the next crisis, India's response was notably more aggressive. In 2019, in response to an attack at Pulwama, India launched an air strike targeting a terrorist training site at Balakot. The Balakot air strike sought to deter Pakistan by crossing multiple new thresholds. India used airpower against Pakistan for the first time since 1971, reached into Pakistani territory beyond Kashmir, and deliberately sent a strong message to Pakistan's establishment that India will not tolerate any terror activities. That strike, despite its dubious tactical effects, validated for Indian decision-makers the notion that they could use military force to punish Pakistan without triggering a war or nuclear retaliation.

Operation Sindoor took that evolution further. India struck a larger set of initial targets, with more force, and more range of weapons, including cruise missiles and loitering munitions. Whereas in Balakot, the use of air power was a radical departure; in Operation Sindoor, air and ground-launched stand-off weapons had become India's primary tool. India already boasted such capabilities, for example, with its indigenously-produced BrahMos cruise missiles, and Israeli-made Spice bomb kits and Harop loitering munitions. But it made a concerted effort to grow these capabilities since Balakot, most prominently with the procurement of French-made Rafale fighters carrying Scalp air-launched cruise missiles. Its layered, integrated air defences, included the Sudarshan Chakra: S-400 surface-to-air missiles that it imported from Russia.

Defence

Operation Sindoor showcased India's evolving military capabilities through Integrated Multi-Domain Operations; The Indian Army, Navy and Air Force operated under the Integrated Command and Control Strategy (ICCS), enabling real-time coordination across land, air, and maritime domains.

The Air Force deployed the Akash missile system and legacy platforms to neutralise Pakistani drone attacks, the Navy's Carrier Battle Group (CBG) enforced maritime dominance, while the Army countered cross-border drone strikes with layered air defence systems. The operation highlighted India's reliance on homegrown technology, such as the Akashteer system for air defence coordination. These efforts neutralised Pakistan's retaliatory drone strikes and reinforced India's capacity to defend its territory across domains.

India has achieved these defence capabilities with a new defence modernisation strategy. India's defence production has grown at an extraordinary pace since the launch of the "Make in India" initiative. Once dependent on foreign suppliers, the country now stands as a rising force in indigenous manufacturing, shaping its military strength through homegrown capabilities. This shift reflects a strong commitment to self-reliance, ensuring that India not only meets its security needs but also builds a robust defence industry that contributes to economic growth. This commitment to self-reliance and modernisation is reflected in the recent approval by the Cabinet Committee on Security (CCS) for the procurement of the Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS), a significant step in enhancing the Army's firepower. With modern warships, fighter jets, artillery systems, and cutting-edge weaponry being built within the country, India is now a leader in the global defence landscape.

Diplomacy

Operation Sindoor had a significant impact on India's diplomatic relations by reshaping its foreign policy posture and consolidating international support against cross-border terrorism. The operation prompted India to recalibrate its foreign policy amid a changing security environment. India's clear political messaging and calibrated military response earned recognition worldwide as a model of punitive deterrence that avoids full-scale war, which has implications for other nuclear-armed states. This enhanced India's diplomatic stature as a nation capable of measured yet decisive action against terrorism. Following Operation Sindoor, India undertook extensive diplomatic efforts, including dispatching seven all-party parliamentary delegations to 25 countries, including permanent members of the UN Security Council, to explain its position and garner support against Pakistan-backed terrorism.

The United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), the monitoring team of the 1267 Sanctions Committee, and other partner countries in the UN were constituted in 1999 to monitor terrorist outfits. An Indian technical team in the United Nations is trying to get 'The Resistance Front TRF', the outfit suspected to be behind the Pahalgam attack, listed as a terrorist group.

So, Operation Sindoor strengthened India's diplomatic leverage by demonstrating strategic clarity, mobilising international support against terrorism, and enhancing its global image as a responsible security actor, while also navigating complex regional and global diplomatic dynamics. The operation's success was amplified through global diplomatic channels, isolating Pakistan and deterring future provocations.

Decision Making

The operation reflected a paradigm shift in India's decision-making architecture. The operation reflects a strong political commitment to counter-terrorism, emphasizing that national security takes precedence over global diplomatic concerns. As PM Modi stated, "Terror and talks can't go together". Decisions were swift, with Prime Minister Modi articulating a "new normal" in warfare-proactive, technology-driven and proportionate.

The approach after the Pahalgam massacre leadership ensured a balanced operational secrecy with political transparency, ensuring domestic and international legitimacy. By treating cross-border terrorism as an act of war, India set a precedent for direct retaliation against state-backed proxies. The Integrated Air Command and Control System (IACCS) enabled seamless intelligence-sharing between agencies; precision strikes targeted nine terror camps in Pakistan and PoJK, avoiding military installations to prevent escalation. Military and political leaders conducted comprehensive evaluations of potential risks and benefits while considering both domestic and international repercussions.

Conclusion

India's Operation Sindoor is a pivotal moment in its defence policy, illustrating a comprehensive approach that incorporates defence, decision-making, and diplomatic strategies. As India navigates its security challenges, the lessons learned from this operation will likely shape future military and diplomatic endeavours, reinforcing the notion that while sovereignty is paramount, effective responses to external threats must balance military might with strategic diplomacy. Operation Sindoor not only addresses immediate security concerns but also serves as a template for India's changing military engagements. As the geopolitical landscape evolves, the intricacies of such operations will continue to play a vital role in shaping national and international security frameworks. ■

सैन्य पराक्रम एवं निर्णायक नेतृत्व का अभाविप ने किया अभिनंदन

पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध आपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सैन्य बलों द्वारा की गई निर्णायक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने केंद्र सरकार के नेतृत्व और सेना के साहस का अभिनंदन किया है। अभाविप का मानना है कि यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, अपितु भारत की सामूहिक चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं सुरक्षा नीति की स्पष्टता का प्रतीक है।

आपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप ने कहा कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद एवं उसके सहयोगी तंत्र का समूल नाश करना देश एवं मानवता की स्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अभाविप पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों एवं नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा करती है। साथ ही इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में समस्त देशवासियों से आह्वान करती है कि वह शासन एवं प्रशासन द्वारा प्रसारित निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, देश में एकता, संयम एवं समरसता बनाए रखें और राष्ट्रविरोधी ताक़तों के किसी भी षड्यंत्र को सफल न होने दें। आपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक संकल्प है। यह भारत की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और नेतृत्व की दृढ़ता का द्योतक है। अभाविप का प्रत्येक कार्यकर्ता इस घड़ी में देश, समाज एवं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा हुआ है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

माओवाद : अंत की ओर

■ राजीव रंजन प्रसाद

21 मई, 2025 की तारीख माओवाद (नक्सलवाद) के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध हुई है। कथित संगठन का महासचिव बासव राजू, जिसका वास्तविक नाम नंबाला केशव राव था, वह अबूझमाड के जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में अपने इकत्तीस साथियों सहित मार गिराया गया। महासचिव का मारा जाना वस्तुतः माओवादी संगठन की रीढ़ की हड्डी के टूट जाने जैसा है। कौन था बासव राजू? किस पृष्ठभूमि का था? कितना पढ़ा-लिखा था? यह सारे प्रश्न इसलिए बेमानी हो जाते हैं क्योंकि मानवता के हत्यारों की, उसकी नृशंसता से अलग, न तो कोई पहचान होती है न ही होनी चाहिए।

बासव राजू को इस बात के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है कि उसने कुख्यात आतंकवादी संगठन लिब्रेशन टाईगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के साथ गठजोड़ किया और बारूदी सुरंग अर्थात इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का प्रयोग करने का प्रशिक्षण लिया। दो आतंकवादी संगठनों के गठजोड़ से माओवाद बहुत क्रूर और वीभत्स होकर उभरा। रानीबोदली (2007), एर्राबोर (2007), मदनवाड़ा (2009), ताड़मेटला (2010), गादीरास (2010), धौड़ई (2010), झीरम (2013), चिंतागुफा (2017), किस्टरम (2018), श्यामगिरी (2019), मिनपा (2020), टेकुलगुड़ेम (2021) जैसी कितनी ही घटनाओं में माओवादियों ने निरीह ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के जवानों के लहू से बस्तर की धरती को लाल किया। बासव राजू आतंकी रणनीति बनाने में बहुत शातिर था। इसलिए ऐसे हत्यारे जब मारे जाते हैं तो प्रसन्नता का विषय होता है। माओवादी महासचिवों की परिपाटी का बस्तर संभाग में चार दशक अर्थात कोण्डपल्ली सीतारमैया, गणपति और फिर बासव राजू की कारगुजारियों की दास्तान है। यह पीपुल्स वार ग्रुप के आंध्र प्रदेश से बस्तर की ओर पलायन के उस दौर से आरंभ होता है, जब भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) जिसके अंतर्गत 2005 में देश भर के सभी आतंकवादी वामपंथी धडे एक हुए थे।

बासव राजू की मौत के बाद माओवाद क्या दशा-दिशा लेता है, इसे देखना-परखना होगा लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संगठन लाचार हुआ है। विभिन्न राज्यों की सीमा से घिरा अबूझमाड अर्थात माओवादियों का आधार क्षेत्र ही उनका मृत्युगीत लिख रहा है। दशकों से अन्तर्राज्यीय सीमाएं माओवादियों के लिए अपना प्रभावक्षेत्र-कार्यक्षेत्र बनाने के लिए सबसे पसंदीदा स्थली रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बस्तर संभाग के वह परिक्षेत्र जो आंध्र-तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि राज्यों से जुड़े हुए हैं, लाल-आतंक का दंश कई दशकों से झेलते रहे हैं। धीरे-धीरे सुरक्षा बलों के कैंप हर कुछ अवधि में नक्सल आधार क्षेत्र को घेरते, क्षेत्र की नाकाबंदी (एरिया डोमिनेशन) करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं था कि समयपर्यंत माओवादी सिमटते-सिमटते समाप्त हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही माओवादियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई छेड़ दी गई। विचारणीय यह है कि आज जब केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति ने एक दिनांक को निर्धारित कर दिया है कि 31 मार्च, 2026 तक देश से माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तब बासव राजू की मौत के साथ हम यह देख पा रहे हैं कि असंभव सा लगाने वाला लक्ष्य पूर्ति के निकट आ पहुंचा है।

संगठन के महासचिव का मारा जाना एक बड़ी घटना तो है लेकिन माओवादियों को अब तक का सबसे गंभीर नुकसान करेंगुट्टा की पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ों के कारण उठाना पड़ा। इक्कीस दिन चले बड़े अभियान में, जिसके अंतर्गत हुए संयुक्त अभियानों में छत्तीसगढ, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सुरक्षाबलों की सम्मिलित भागीदारी रही, इकत्तीस माओवादी मार गिराए गए। करेंगुट्टा की पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ों से हुई कैडर हानि के साथ ही लाल-आतंकवाद ने यहां जो कुछ खोया है, इससे उनके संगठन की लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई है। इस सफलता का सबसे बड़ा हासिल यह है कि अब माओवादी किसी भी क्षेत्र को अधिकार के साथ अपना आधार क्षेत्र नहीं कह सकते।

इसे ठीक से जानने के लिए आधार क्षेत्र को पहले समझते हैं। माओवादियों का आधार क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है, जहां वह संगठित होकर अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर लेते हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर दुर्गम जंगलों, पहाड़ों और ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जहां राज्य की उपस्थिति कमजोर होती है। इन आधार क्षेत्रों में माओवादी अपने प्रशिक्षण शिविर, शस्त्र निर्माण और निर्णय लेने की गतिविधियां संचालित करते हैं। इसके साथ-साथ यह परिक्षेत्र हथियारों, रसद आपूर्ति और गुरिल्ला युद्ध के लिए रणनीतिक ठिकाने भी होते हैं।

माओवादियों ने देश भर के अनेक क्षेत्रों को आधार क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, जहां सुरक्षित रह कर वह राज्य का मुकाबला कर सकें, लेकिन अधिकांशतः वह असफल रहे। इन प्रयासों में पहले पलामू, लातेहार और गया जैसे झारखंड और बिहार के वनाच्छादित परिक्षेत्र थे, परंतु यहां प्रभाव बनाने के बाद भी माओवादी आधार क्षेत्र निर्मित नहीं कर सके। पश्चिम बंगाल के झारग्राम और पुरुलिया जैसे क्षेत्रों में भी प्रयास किया गया, लेकिन वहां भी असफलता प्राप्त हुई। ओडिशा के कोरापुट, मल्कानगिरी, कंधमाल आदि क्षेत्रों में भी माओवादी अत्यधिक सक्रिय रहे, लेकिन यहां भी वह अपने सुरक्षित ठिकाने नहीं तलाश सके। तेलंगाना-आंध्र के मुलुगु के जंगलों में भी प्रयास हुआ लेकिन ग्रे-हाउंड्स फोर्स के सटीक प्रहारों ने उनकी कमर तोड़ दी। माओवादियों का सबसे बड़ा सपना दण्डकारण्य क्षेत्र को कथित लिब्रेटेड ज़ोन बनाने का था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आपस में जुड़े घने जंगल और दुर्गम पर्वतीय हिस्से आते थे। लेकिन यहां भी उनकी कमर टूट गई है।

वास्तविकता को रेखांकित किया जाए तो केवल अबूझमाड के जंगल ही माओवादियों के लिए अब तक सुरक्षित पनाहगाह बने रह सके थे। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में विद्यमान आधार क्षेत्र छीने जाते ही माओवादियों की बंदूक वाली बिग्रेड को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। चार दशकों से जारी माओवाद ने अपने विभिन्न अभियानों में बड़ी संख्या में स्वचालित हथियार लूटे हैं, तस्करी की है और समानांतर रूप से कारखाने बना कर तरह-तरह के देशी हथियार स्वयं

बनाते रहे हैं। इस कारण कई विशेषज्ञ यह मानते थे कि अब तक सुरक्षाबलों का सामना माओवादी बटालियनों से आमने-सामने की लड़ाई में नहीं हुआ है और जब भी ऐसा होगा तो जंगल-पहाड़ों से पूरी तरह परिचित होने के कारण माओवादी गुरिल्ले जवानों पर भारी पड़ सकते हैं। माओवादियों को हमेशा यह लगता था कि अबूझमाड में लड़ाई सबसे आखिरी में होगी, लेकिन सुरक्षाबालों ने देश भर में जारी माओवाद उन्मूलन के समानांतर इस दुर्गम वन-परिक्षेत्र में अपने अभियानों को सघन किया। बदली हुई रणनीति के तहत ऐसा लगता है कि जहां आखिरी लड़ाई माना जा रहा था, पहल वहीं से हुई और बहुत ही आक्रामकता के साथ आपसी संयोजन करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जैसे विविध सुरक्षा बल माओवाद की रीढ़ पर ही प्रहार करने के लिए अबूझमाड के भीतर बढ़ चले हैं। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी के चारों ओर लगाई गई बड़ी मात्रा में आईईडी, इस बात का द्योतक थी कि तैयारी पूरी है, ईंट का जवाब देने के लिए माओवादियों के पत्थर तैयार हैं। प्रश्न उठता है कि माओवादी यहां ध्वस्त कैसे हुए? क्या अब भी उनका अस्तित्व है अथवा वह लड़ने की स्थिति में हैं?

कर्रेगुट्टा की पहाड़ी जिसका विस्तार ही लगभग साठ किलोमीटर के दायरे में है, यहां जब माओवाद का गढ़ ध्वस्त हुआ, उससे पहले ही स्पष्ट होने लगा था कि माओवादी अब पीछे हट रहे हैं। माओवादियों के अपने बैकडोर चैनल खोलकर उनका शहरी माओवादी कैडर छटपटा कर तेलांगाना में सभाएं कर रहा था, सरकार पर दबाव डाल रहा था कि किसी तरह से बातचीत आरंभ हो जाए और सुरक्षाबल अपने अभियान रोक दें। ऐसे समय छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से जितनी दृढता दिखाई वह आवश्यक कदम था। इस बीच माओवादियों ने भी अनेक बार पर्चे जारी कर, तो एक बार पत्रकार को साक्षात्कार दे कर, यह प्रयास किया कि किसी तरह सुरक्षाबल अपनी कार्रवाई रोक दें और सरकार माओवादियों अथवा शहरी माओवादियों के साथ वार्ता के लिए तैयार हो जाए। यदि ऐसा होता तो यह माओवादियों को ऊर्जा देने जैसी बात होती, वह अपने बिखरते संगठन और ताकत को समेटने के लिए यही समय चाहते हैं, बातचीत तो केवल एक बहाना भर है। इसी मध्य एक माओवाद समर्थक, जो बड़े वकील भी हैं, माओवाद उन्मूलन को इस बात से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद जनजातीयों का पलायन होगा, सरकार जमीनें छीन लेगी आदि। इस तरह की टूल किट को हल्के में लेना ठीक नहीं है क्योंकि यह कब अपने तंत्र के बल पर वैश्विक आवाज बन जाएं, कहा नहीं जा सकता।

इन अवरोधकों को राज्य तथा केंद्र की सरकारों ने बहुत सूझ-बूझ से पार किया और माओवादियों को केवल आत्मसमर्पण का विकल्प देते हुए अभियान को जारी रखा। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि माओवाद के कारण बस्तर से बड़ी संख्या में जनजातीयों का पड़ोसी राज्यों में पलायन हुआ है। जनजातीयों के नाम की कथित लड़ाई लड़ने वाले माओवादियों ने ही अनेक जनजातीय परिवारों को घर और जमीन से बेदखल किया है। सब ओर से हताश माओवादियों ने एक पर्चे में पुलिस से अपील की कि वह कार्रवाई न करें। समय देखिए, लाल-हत्यारे उसी पुलिस के आगे गिड़गिड़ाने के लिए बाध्य थे, जिन्हें वह अब तक कुछ समझते ही नहीं थे, असंख्य सिपाही उनके द्वारा गला रेत कर मारे गए या बारूदी सुरंग विस्फोट करके मार दिए गए। कई ऐसे ग्रामीण हैं, जिन्हें अपना घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके कोई परिजन पुलिस में हैं। किसी पुलिस वाले से केवल भूल वश भी बात करने पर कितने ही जनजातीय मुखबिर बता कर मार दिए गए। ऐसे में स्पष्ट है कि माओवादी स्वयं के लिए सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं, खुद को बेचारा बता कर अवसर चाहते हैं।

यहां संज्ञान में लेना चाहिए कि जब अभियान समाप्त हुआ तब माओवादियों के पास से न केवल स्वचालित हथियार मिले अपितु आईईडी, कारडेक्स, डेटोनेटर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही माओवादियों की चार तकनीकी इकाइयों को भी नष्ट किया गया है, जिसका उपयोग हथियारों एवं आईडी आदि के निर्माण के लिए किया जाता था। माओवादियों की इस पहाड़ी पर उपस्थिति

कितनी मजबूत थी, इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ढाई सौ से अधिक प्राकृतिक और मानवनिर्मित बंकर नष्ट किए गए, अनेक ऐसी गुफाएं मिली, जहां से माओवादी छिपकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। बारह हजार किलोग्राम से अधिक का राशन भी बरामद हुआ।

देश के गृहमंत्री अमित शाह ने तो देशभर से माओवाद की समाप्ति की बात की है, तब क्या केवल अबूझमाड के भीतर की लड़ाई पर्याप्त है? क्या आधार क्षेत्र छिन जाने के बाद माओवादी किसी अन्य क्षेत्र पर संगठित होकर अपनी गतिविधि संचालित नहीं कर सकेंगे? यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ज्वलंत प्रश्न है। इसे समझने के लिए जानना होगा कि केवल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखण्ड जैसे राज्यों में ही माओवादियों को समाप्त करने की मुहिम नहीं चल रही, अपितु दूर-सुदूर के जंगल भी, छोटे-छोटे ठिकाने भी इस अभियान में दरकिनार नहीं किए गए। उदाहरण कर्नाटक का है, जो उस लाल गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो माओवादियों के सपने को चीन से आरंभ कर नेपाल के रास्ते से होते हुए श्रीलंका तक जोड़ता था।

यह 1980 का दशक था, जब माओवादियों के कदम भारत के दक्षिणी हिस्सों में मजबूत हो रहे थे। इन परिक्षेत्रों में सुरक्षित पनाहगाह की खोज में उन्हें पश्चिमी घाट के दुर्गमतम क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। केरल में वामपंथ की पृष्ठभूमि पहले से ही मजबूत थी। साथ ही कर्नाटक के जंगल भी तब लाल-सलाम के नारों से गूंजने लगे थे। पश्चिमी घाट के चिक्कमंगलुरु, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, शिमोगा और कोडागु जिलों में इसी दौरान से माओवाद के खूनी पंजे मजबूत हुए। 2005 में हेब्री में पुलिस जीप में बमबारी, 2007 में अगुंबे में एक सब-इंस्पेक्टर की हत्या, 2008 में नादपलु में भोज शेट्टी और उनके रिश्तेदार सदाशिव शेट्टी की हत्या की नृशंस घटना के माध्यम से कर्नाटक को दहलाया जाता रहा।

माओवादियों के सतत विस्तार और प्रभाव क्षेत्रों का अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी घाट उनके लिए रिजर्व क्षेत्र की तरह था। किसी समय भागने (स्थापित आधार क्षेत्र छोड़ कर अन्य स्थान पर जाना) की नौबत आ जाए या अबूझमाड से निकलने के लिए बाध्य होना पड़े, तब वह इन जंगलों की ओर बढ़ना चाहते थे। 2016 में यहां सक्रिय समूहों पर दबाव पड़ा, कुछ ने आत्मसमर्पण किया तो एक समूह केरल की ओर चला गया। लगातार नाकामियों के कारण केरल प्रवेश से भी कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि इससे उलट पश्चिमी घाट के पहाड़ों-जंगलों से माओवादियों का दबाव कम होने लगा।

2023 में कर्नाटक परिक्षेत्र में पुनः सिर उठाने की कोशिश में लगा माओवादी कमांडर विक्रम गौड़ा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। विक्रम का मारा जाना बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि इन क्षेत्रों में उसका प्रभाव था। 2024 में माओवादी संगठन के पश्चिमी घाट जोनल कमेटी के सदस्य अंगाड़ी सुरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे क्षेत्र में माओवादी पूरी तरह हाशिए पर चले गए। पुलिस और प्रशासन ने अंगाड़ी सुरेश का भरपूर लाभ लिया और उससे अन्य माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण करने की अपील भरे पत्र और पर्चे लिखवाए। इन पर्चों का लाभ यह हुआ कि 8 जनवरी 2025 को महत्वपूर्ण माओवादी सरगना वंजाक्षी सहित पांच अन्य माओवादियों ने बेंगलुरू में आत्मसमर्पण कर दिया। यह समूह कर्नाटक में माओवादी सक्रियता के लिए जिम्मेदार आखिरी दल था। अब भी क्षेत्र के केवल दो शेष रहे माओवादी फरार थे। बीते दिनों श्रृंगेरी के किगा गांव में रहने वाले माओवादी कोथेहुंडा रविंद्र और कुंडापुरा गांव के रहने वाले थोंबुटु लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी पूजार्थी ने समर्पण किया; जिसके बाद कहा जा सकता है कि कर्नाटक अब पूरी तरह माओवाद से मुक्त हो चला है।

सुरक्षा बलों ने यदि सौ अभियान किए तो सौ के सौ में उन्हें सतर्क, सटीक और सफल होना आवश्यक है लेकिन जाने-अनजाने की एक चूक वह होती है, जिसकी अपनी असफलताओं के बाद भी माओवादी प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसका एक उदाहरण था सुरक्षाबालों को मिल रही अनेक सफलताओं के बीच 6 जनवरी, 2025 की घटना। बीजापुर में माओवादी उग्रवाद उन्मूलन की कार्रवाई में बड़ी सफलता अर्जित करते हुए जवानों ने पांच माओवादियों को ढेर कर दिया था। पूरे क्षेत्र की सघन सर्चिंग करने के उपरांत जवान अपने कैंप की ओर लौट रहे थे। डीआरजी के जवानों को वापस

लाने के लिए जो वाहन भेजा गया था, उसे माओवादियों ने निशाना बनाया और कुटरू क्षेत्र में अंबेली ग्राम के निकट आईईडी में विस्फोट करा दिया। यह धमाका इतना अधिक शक्तिशाली था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। न केवल वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि उसका एक हिस्सा निकट के पेड़ पर लटका हुआ देखा गया। सड़क के मध्य दस फुट से अधिक गहरा गड्ढ़ा हो गया। दंतेवाड़ा डीआरजी के आठ जवान और एक वाहन चालक इस घटना में बलिदान हो गए।

2024-25 के दौरान अनेक बड़ी घटनाएं हुई, मुठभेड़ हुई किन्तु अब परिणाम बदलने लगे थे। अब बलिदानी जवानों की संख्या नगण्य थी, तो बड़ी संख्या में माओवादी ढेर किए जाने लगे। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्सल उन्मूलन अभियान सही दिशा पर है। इसी वर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 अप्रैल को आधिकारिक रूप से बताया कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल-2024 में 38 हो गई। कुल प्रभावित जिलों में से, सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के चार जिले (बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा), झारखंड का एक (पश्चिमी सिंहभूम) और महाराष्ट्र का एक (गढ़चिरौली) शामिल है। इसका सामान्य सा अर्थ है कि माओवाद अपनी आखिरी सांसे ले रहा है।

इसके बाद भी यह समझना ही होगा कि विचारधारा की लड़ाई में अंतिम विजय तभी हो सकती है जब इस रावण की नाभि में जाकर तीर लगे। सुरक्षाबल अपना काम कर रहे है लेकिन माओवादी मोर्चे की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका है उस आधे मोर्चे की, जिसका उल्लेख एक बार दिवंगत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत ने किया था।

ध्यान रहे कि जब कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर सुरक्षाबल माओवादियों से लोहा ले रहे थे, ठीक उसी समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एवं वहां के विपक्षी दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव माओवादियों से शांति वार्ता की मांग कर रहे थे। इस समय तेलंगाना में कई माओवादी समर्थक समूह सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने सिविल सोसाईटी जैसी खाल ओढ ली है। यह परिस्थिति अपेक्षित है लेकिन इसी समय छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बौद्धिक मोर्चे का तोड़ उन्हीं के तौर-तरीके से निकाला। तथ्य और तर्क बहुत प्रभावी तरीके से सामने लाए गए। सितंबर-2024 को बस्तर से लगभग पचपन माओवादी पीड़ित दिल्ली पहुंचे और जंतर-मंतर पर उन्होंने अपनी व्यथा देश के सामने रखी। इतना ही नहीं, उसी संध्या को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी व्यथा से सभी को अवगत कराया। माओवादियों से पीड़ितों ने यह प्रश्न छात्रों के सामने रखा कि अध्ययनशील और विचारवान लोगों को समस्या की पहचान होनी चाहिए, न कि उन्हें किसी विचारधारा अथवा एजेंडा के बहाव में आना चाहिए। अनेक पीड़ितों ने अपनी कहानी बताई कि जिस जल, जंगल और जमीन के नारों की बात सामने रख कर माओवाद को सही बताया जाता है, उसी के कारण आज वह अपने ही जंगल से घबराते हैं कि कब किस पेड़ के नीचे लगाया गया कोई आईईडी या प्रेशर बम फट जाए और वह अपनी जान गंवा दें। ग्रामीणों ने बताया कि माओवादियों ने किस तरह स्कूलों को नष्ट कर उनकी पीढ़ी को अनपढ़ बनाना चाहा, सड़कों और संचार के माध्यमों को नष्ट कर उन्हे शेष दुनिया से काट कर रखा। कई पीड़ित जो अब चलने-फिरने से भी लाचार हैं, उन्होंने न्याय-व्यवस्था का प्रश्न कैंपस में उठाया और पूछा कि कोई भी बौद्धिक जमात उस अन्याय की बात क्यों नहीं करता जो माओवादियों द्वारा कथित जन-अदालत लगा कर बस्तर के जंगलों में की जाती है।

माओवाद ने देश भर को और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर परिक्षेत्र को लाशों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया है। आज जब माओवाद अपनी सांसें ले रहा है तो इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नासूर का लेश मात्र हिस्सा भी बचा न रह जाए। एक जागरूक नागरिक के रूप में बौद्धिक आतंकवाद का भी हर मोर्चे पर मुकाबला करना होगा क्योंकि बंदूक वाले लाल-आतंकवादी आज तक कलम वाले आतंकवादियों के दम पर ही जिंदा रहे हैं। अपेक्षा है कि माओवादियों का मृत्युगीत जब थमेगा, शांति और विकास की रोशनी बिखेरता नया सूरज माओवाद से पीड़ित परिक्षेत्रों में उजाला फैलाता मिलेगा। ■

सुशासन से पस्त बंदूक का शासन

■ अरविंद कुमार मिश्रा

तीन दशक में पहली बार ऐसा हुआ है, सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन के महासचिव स्तर के किसी माओवादी सरगना को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में मारा गया माओवादियों का सबसे बड़ा सरगना बासवराजू भाकपा (माओवादी) का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य था। उसे माओवादी आंदोलन की रीढ़ कहा जाता था, ऐसे में उसका मारा जाना वामपंथी उग्रवाद के ताबूत में अंतिम कील की तरह है। सुरक्षा बलों को यह सफलता उस अबूझमाड़ में मिली, जिसे माओवाद की अंतिम शरणस्थली माना जाता है। इसके पहले छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर माओवादियों के कथित गढ़ को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। गलगम और कर्रेगुट्टा लंबे समय से माओवादियों का गढ़ रहा है। यहां माओवादियों के 216 ठिकानों और बंकर को ध्वस्त कर दिया। आतंक के बल पर सत्ता हासिल करने का स्वप्न देखने वाले माओवादियों के विरुद्ध सटीक एवं ठोस कार्रवाई जिस तरह से जारी है, उससे माओवाद की समस्या का जड़ से उन्मूलन तय है।

अंत्योदय से लोकतंत्र की जीत

एक तरफ पुलिस एवं अर्धसैनिक बल माओवादियों को उनकी भाषा में ही जवाब दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों की माओवाद से पीड़ित क्षेत्रों में विकास से जुडी जनकल्याणकारी योजनाएं बंदूक के शासन पर सुशासन की विजय सुनिश्चित करती जा रही है। केंद्र सरकार ने 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना को मंजूरी देकर माओवाद से ग्रस्त क्षेत्रों तक विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से सड़क निर्माण, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। माओवाद से पीड़ित क्षेत्रों में नियद नेल्ला नार योजना के जरिए 17 विभागों की 53 योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल जैसे विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में अनूसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। स्वतंत्रता के बाद आईं कई सरकारों ने वनों से जुड़े

क्षेत्रों का सिर्फ दोहन किया। इससे स्थानीय निवासियों सहित एक बड़ा वर्ग न सिर्फ विकास की मुख्यधारा से वंचित हो गया, बल्कि देश विरोधी ताकतों ने भी उसे गुमराह किया। वोट बैंक की राजनीति से माओवाद को खाद पानी मिलता रहा। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से दूरस्थ क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव आया है।

जनजातीय क्षेत्रों में विकास

माओवाद का दंश सबसे अधिक यदि किसी को झेलना पड़ा है तो वह जनजातीय समाज है। माओवाद और विदेशी ताकतों से प्रायोजित रक्तरंजित वामपंथी विचारधारा ने कभी कथित जनजातीय अस्मिता तो कभी मतांतरण की आड़ में जनजातीय लोगों को माओवाद की आग में झोंकने का काम किया। आज देश में यदि माओवाद अंतिम सांस ले रहा है तो उसके पीछे राज्य एवं केन्द्र सरकार की अंत्योदय आधारित वह नीतियां हैं, जिनसे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जनजातीय कार्य मंत्रालय के गठन के साथ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला शुरू हुई, जिसका असर जमीन पर देखा जा सकता है। वर्तमान केंद्र सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास को लेकर पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष जैसी कई महत्वाकांक्षी योजना संचालित कर रही है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश में जो सड़कें बन रही हैं, उनमें 50 प्रतिशत सड़कें छत्तीसगढ़ में हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना से छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह कई नीतियों का सर्वाधिक लाभ जनजातीय समाज के लोगों को मिल रहा है, उनके जीवन स्तर में गुणवत्ता आई है।

जीरो टॉलरेंस नीति

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना अंतर्गत कवर किए जाने वाले जिलों से परिलक्षित होती है। अप्रैल 2021 में एसआरई जिलों की संख्या घटकर 70 हो गई।

हमें अपने जवानों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

***नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री*

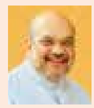

माओवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में तीन दशकों में पहली बार हमारे जवानों ने एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं।

***अमित शाह**, केंद्रीय गृह मंत्री*

बस्तर शीघ्र ही पूरी तरह से माओवाद से मुक्त हो जाएगा। गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से हमारी सरकार की नीति रही है। प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में सिमटा माओवाद अब अंतिम सांस ले रहा है।

***विष्णु देव साय**, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़*

माओवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अर्धसैनिक बलों तथा स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा माओवाद से पीड़ित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों तथा अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय सुदृढ़ करने की जो पहल की गई, उससे माओवाद विरोधी मुहिम प्रभावी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आत्मसमर्पण और पुनर्वास को काफी आकर्षक बनाया है, जिससे कई माओवादी मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन में संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण हथियार बन रहा है।

वसूली तंत्र पर प्रहार

माओवादी उग्रवादियों के आर्थिक तंत्र पर चोट किए बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। माओवादी

समस्या का दंश झेल रहे राज्यों में माओवादियों द्वारा कारोबारियों, उद्योगों से वसूली की लगातार जानकारियां सार्वजनिक होती रही हैं। एक आंकड़े अनुसार झारखंड में ही नक्सली लगभग तीन सौ करोड़ रुपए हर वर्ष वसूलते हैं। अलग-अलग राज्यों में यह डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली करते हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इस पैसे का उपयोग माओवादी संगठन के विस्तार और हथियार खरीदने में किया जाता है। ऐसे में इनके वित्तीय ढांचे को उखाड़ने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर निगरानी और बढ़ाने की जरुरत है।

माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ एकजुटता जरूरी है। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बनी माओवादी गतिविधियों को जितनी जल्दी हो समूल समाप्त करना होगा। माओवादी हिंसा को एक खास बौद्धिक वर्ग ने सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिश की है। माओवादियों के गिरोह भले ही जंगलों में हों लेकिन इनके शहरी नेटवर्क पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इसका हमेशा के लिए समाधान संभव नहीं है। वनों पर निर्भर जनजाति और स्थानीय समाज माओवाद जैसी किसी भी हिंसात्मक विचारधार का पोषक नहीं हैं, लेकिन तरह-तरह के प्रलोभन और भय दिखाकर उन्हें पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। माओवादी हिंसा से ग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को कायम रखते हुए सुशासन का उजाला माओवाद को जड़ से खत्म करने में सहायक होगा।

सुनिश्चित पुनर्वास माडल

छत्तीसगढ़ सरकार ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु बेहतरीन नीति लागू की है। बंदूक छोड़कर शांति की राह पर लौटे माओवादियों के लिए पंद्रह हजार पीएम आवास बनाए जाने हैं, इनमें 2500 आवास की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसी तरह नई औद्योगिक नीति में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों को स्वरोजगार खड़ा करने के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया। बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक की गोलियां गूंजती थी, वहां कुछ माह पहले हुए बस्तर ओलंपिक में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए तालियों की गूंज माओवाद पर लोकतंत्र की जीत का शंखनाद था। बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 खिलाड़ियों का पंजीयन बताता

है कि बस्तर माओवाद नहीं विकासवाद और खुशियां चाहता है।

बेनकाब होते राष्ट्र विरोधी तत्व

माओवादियों का उद्देश्य क्या है? उनकी मांग क्या है? वह संवाद की जगह हिंसा का रास्ता क्यों अपनाते हैं? वह संविधान की जगह बंदूक का शासन क्यों चाहते हैं? 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से माओवाद की शुरुआत के साथ उसके समर्थकों से यह प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से माओवादी समर्थन की बौद्धिक जुगाली करने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग कभी इस बात पर खुलकर नहीं बोलते। आज जब माओवाद का रक्तरंजित चेहरा सबके सामने है, तब भी वह खामोश है। माओवादियों द्वारा लिखे गए स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन में वामपंथी उग्रवाद के समर्थकों ने लिखा है "हमारा उद्देश्य सशस्त्र युद्ध के जरिए भारत की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना है। युद्ध से ही समस्या का समाधान करना है। माओवादी संगठनों का मुख्य कार्य भारतीय सेना, पुलिस और संपूर्ण नौकरशाही व्यवस्था को युद्ध द्वारा नष्ट करना है।"

सवाल है कि वामपंथी उग्रवाद में अपनी जान गंवाने वाले लोग कौन हैं? माओवाद के बिछाए विस्फोटक आईईडी ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वाले तथा दिव्यांग होते लोग कौन हैं? क्या वह इंसान नहीं हैं? क्या वह जनजातीय समाज से नहीं हैं। यह सवाल उन बौद्धिक आततायियों से पूछे जाने की जरुरत है जो गरीब और भोले-भाले लोगों को हिंसा के रास्ते में धकेलने के लिए एक ऐसी विचारधारा का पाठ पढ़ाते हैं, जिसका न तो भारत और न ही मानवता से कोई सरोकार है। जो लोकतंत्र नहीं बंदूक का शासन चाहती है। आज बस्तर में सुरक्षा बल अपने पराक्रम से भले ही माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंके, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और बौद्धिक होने का लिबास ओढ़कर रक्तरंजित वामपंथी विचारधारा के लिए काम करने वाली देश विरोधी ताकतों को पहचानना होगा। जंगलों में माओवादी जहां भोले-भाले जनजातियों को डराते-धमकाते हैं, इससे ठीक उलट शहरी माओवादी बौद्धिक और लच्छेदार बातें कर विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों से लेकर हर उस संस्थान तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जहां से देश का भविष्य गढ़ा जाता है। ऐसे कथित बौद्धिकों की पहचान और बहिष्कार करके उनका समूल नाश करना होगा तभी माओवादी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा। ■

जेएनयू में संयुक्त सचिव सहित 24 काउंसलर पदों पर अभाविप की जीत

देश की राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने संयुक्त सचिव पद के साथ ही 42 में से 24 काउंसलर पदों पर जीत हासिल की है। अभाविप ने अबकी बार जेएनयू में वर्षों से स्थापित तथाकथित वामपंथी प्रभुत्व को ध्वस्त करते हुए 'लाल दुर्ग' में जिस तरह से भगवा परचम फहराया, वह न केवल जेएनयू के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित छात्र आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

मैं इस जीत के लिए जेएनयू के सभी छात्रों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र-प्रथम के विचार को समर्थन दिया, समाज और देश को जोड़ने के विचार को समर्थन दिया, अभाविप को समर्थन दिया और हमारे इस अभियान का हिस्सा बने, जिससे यह जीत संभव हुई। यह जीत अभाविप के उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जो दशकों से जेएनयू परिसर में वामपंथ की जहरीली राजनीति के विरोध में लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। यह जीत उन सभी छात्रों की आशाओं का प्रतीक है जो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह विजय एक ऐसे जेएनयू के निर्माण की ओर पहला कदम है, जहां प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर, सम्मान और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का वातावरण प्राप्त हो। अभाविप के प्रति आभारी हूं कि जिसने एक सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाले लड़के को नेतृत्व करने का मौका दिया। जीत के साथ यह मेरा दायित्व है कि जेएनयू की जो नकारात्मक छवि बनी है, उसको सुधारने और सही करने का काम करेंगे।

***वैभव मीणा**, नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव*

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के परिणामों की घोषणा गत 27 अप्रैल को हुई, जिसमें अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय पैनल के संयुक्त सचिव पद पर शानदार जीत हासिल करके अभाविप उम्मीदवार वैभव मीणा ने वामपंथी संगठनों को चुनौती दी। साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के पदों पर भी अभाविप ने कांटे की टक्कर दी, जिससे अंतिम चरण तक अभाविप के उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में बने रहे। जेएनयू के छात्र वर्ग में राष्ट्रवादी सोच के प्रति बढ़ती व्यापक स्वीकृति के परिणामस्वरूप 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 24 सीटों पर अभाविप को सफलता मिली। जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस में अभाविप को 25 वर्षों बाद जहां दो सीटों पर विजय हासिल हुई, वहीं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में भी अभाविप ने दो सीटों पर सफलता प्राप्त कर नया राजनीतिक परिदृश्य गढ़ा है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभाविप ने कई स्कूलों में निर्विरोध जीत भी हासिल की, जिसमें स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एकमात्र सीट पर सुरेंद्र बिश्नोई, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की तीनों सीटों पर प्रवीण पीयूष, राजा बाबू और प्राची जायसवाल और स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन की सीट पर गोवर्धन सिंह निर्विरोध विजय हासिल करने वाले उम्मीदवार के रूप में सामने आए।

अभाविप को मिली विजय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप जेएनयू इकाई के अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे ने कहा कि यह विजय न केवल अभाविप के अथक परिश्रम और राष्ट्रवादी सोच पर विद्यार्थियों के विश्वास का प्रमाण है, बल्कि यह उन सभी छात्रों की जीत है जो शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हैं। जेएनयू में वर्षों से स्थापित एकपक्षीय विचारधारा के विरुद्ध यह लोकतांत्रिक क्रांति है। अभाविप छात्र हितों और राष्ट्र पुनर्निर्माण के अपने संकल्प के साथ कार्य करती रहेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। असम ।

बराक संस्कृति को दर्शाने वाली भव्य शोभायात्रा का आयोजन

बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बराक सांस्कृतिक महोत्सव में एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) असम प्रांत तथा राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शोभायात्रा तेज आंधी और वर्षा के बावजूद सफलता के साथ संपन्न हुई। बराक सांस्कृतिक शोभायात्रा का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (दक्षिण असम प्रांत) के प्रांत प्रचारक गौरांग राय ने किया। पांच सौ से अधिक छात्र-छात्राओं के साथ ही आम नागरिक के साथ संपन्न हुई शोभायात्रा का मुख्य उद्देश्य बराक उपत्यका (घाटी) की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना और उसकी गरिमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा। गत 17 अप्रैल को शोभायात्रा का आरंभ सिलचर जिले के टाउन क्लब से प्रातः सात बजे हुआ। तेज आंधी और वर्षा होने के बावजूद शोभायात्रा

सफलता के साथ संपन्न हुई। शोभायात्रा में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री कमलेश सिंह, असम प्रांत के संगठन मंत्री अनूप कुमार, तुषार भौमिक और बराक घाटी के विभिन्न जिलों के शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी सहभागी बने। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

Upholding the Honor of Our Nation

A CONSTITUTIONAL AND LEGAL PERSPECTIVE

■ Dr. Pradeep Kumar

Every citizen of India has a moral and legal obligation to respect the nation, its Constitution, and its national symbols, including the National Flag and the National Anthem. This duty is enshrined in Article 51A(a) of the Indian Constitution, which mandates every Indian to uphold the dignity of national symbols. Alongside constitutional mandates, various legal provisions ensure that the reverence for these national emblems is preserved. This article explores the significance of respecting our nation and its symbols while highlighting the legal framework that reinforces this duty.

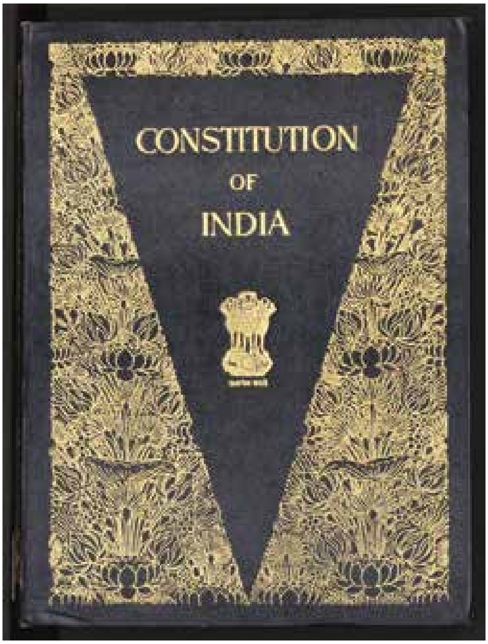

Respect for the Nation and Its Ideals

Respect for the nation goes beyond mere words; it involves commitment to upholding constitutional values, maintaining unity, and promoting national integrity. Article-14 guarantees equality before the law, emphasizing the need for citizens to abide by constitutional principles. Further, Article-368 affirms the supremacy of the Constitution, which every citizen is duty-bound to respect. Any attempt to disrespect or defy constitutional provisions can have legal consequences under various laws.

Honoring the National Flag : A Symbol of Pride and Sovereignty

The National Flag represents India's sovereignty and unity. To maintain its honor, The Prevention of Insults to National Honour Act-1971, penalizes any act of disrespect towards the Flag. Additionally, The Flag Code of India-2002, lays down the correct manner of displaying and handling the Flag. Legal provisions such as Section-124A of the IPC (Sedition) also criminalize acts that show contempt toward national symbols, reinforcing the need for reverence.

The Supreme Court, in Union of India v. Naveen Jindal (2004), recognized the right of citizens to hoist the National Flag under Article 19(1)(a) (Freedom of Speech), provided it is done with due respect. This judgment reflects the balance between individual rights and the collective duty of honoring national symbols.

Responsibilities While Handling the National Flag

To ensure the dignity of the National Flag, the following guidelines from The Flag Code of India, 2002 must be followed: The Flag should always be displayed in a position of honor and should not touch the ground or be used as drapery, clothing, or decoration. The Flag should not be placed upside down or defaced in any manner. When hoisted, it should be given the highest position and flown freely. Damaged or soiled Flags should not be displayed and must be disposed of in a respectful manner by burning or burying. The National Flag should always be hoisted briskly and lowered ceremoniously.

Respecting the National Anthem

A Mark of Patriotism The National Anthem embodies India's cultural and historical ethos. Any act of disrespect towards it is an offense under Section 3 of The Prevention of Insults to National Honour Act-1971. The Supreme Court has also addressed issues regarding the National Anthem in Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986), ruling that while citizens should respect the Anthem, compelling them to sing it against their religious beliefs violates Article-25 (Freedom of Religion).

In another landmark case, Shyam Narayan Chouksey v. Union of India (2018), the Supreme Court held that playing the National Anthem in cinema halls is not mandatory but should be respected whenever played. This decision emphasizes that respect for national symbols should be a voluntary act of patriotism rather than forced compliance. Legal Consequences of Disrespecting National Symbols To maintain the sanctity of the nation and its symbols, several statutory provisions penalize acts of disrespect: The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act- 1950 prohibits the misuse of national emblems. The Representation of the People

In many parts of the world, respect for national symbols such as the flag and the national anthem is mandated by stringent laws that impose severe penalties for any perceived act of disrespect, a stark contrast to the more liberal framework in India.

Act-1951 disqualifies individuals involved in offenses against the Constitution. The Indian Penal Code-1860, under Sections-153A and 153B, punishes those who promote enmity against constitutional values. The Information Technology (IT) Act-2000, extends protection to digital platforms, ensuring national symbols are not disrespected online. Respecting our nation, National Flag and National Anthem is not just a fundamental duty, but a reflection of our commitment to India's democratic and sovereign values. The legal provisions and judicial pronouncements ensure that these symbols are accorded the dignity they deserve. As responsible citizens, it is imperative to uphold these values, fostering unity, integrity, and patriotism in every sphere of life.

In many parts of the world, respect for national symbols such as the flag and the national anthem is mandated by stringent laws that impose severe penalties for any perceived act of disrespect, a stark contrast to the more liberal framework in India. In countries like Russia, the legal system is uncompromising when it comes to protecting national emblems; any act of desecration or disrespect toward the flag is not only socially condemned, but also punishable by strict legal measures including fines, imprisonment, or even forced labor under specific articles of the Russian Criminal Code. In Russia, the

In Russia, the law requires citizens to stand for the national anthem without exception, and failure to do so is seen as a direct affront to state authority, leaving little room for individual interpretation or dissent.

law requires citizens to stand for the national anthem without exception, and failure to do so is seen as a direct affront to state authority, leaving little room for individual interpretation or dissent. Similarly, certain European nations such as France and Germany have adopted a model where the desecration of national symbols is met with harsh sanctions-French law, for example, imposes hefty fines and potential jail time for actions considered disrespectful to the national flag, while Germany's legal provisions strictly prohibit the misuse of national emblems, ensuring that any deviation from the established protocols is swiftly and rigorously penalized.

These countries view their national symbols as inviolable markers of unity and sovereignty, protected by laws that reflect a collective consensus on national identity, often at the expense of personal liberties. In stark contrast, India's approach to respecting national symbols is underpinned by a constitutional commitment that balances reverence for national ideals with individual freedoms. Enshrined in Article-51A(a) of the Indian Constitution, the duty to honor the nation, its flag, and its anthem is supported by legal frameworks such as The Prevention of Insults to National Honour Act-1971, and guidelines articulated in the Flag Code of India-2002. However, Indian law emphasizes voluntary respect and personal commitment to national values rather than rigid enforcement. Judicial pronouncements have underscored that while citizens are expected to respect these symbols, such respect should not come at the cost of fundamental rights, as evidenced by landmark rulings that protect religious freedoms and freedom of expression. Consequently, although India maintains legal provisions to deter overt disrespect through penalties and fines, the overall legal and social environment encourages patriotism as a matter of personal choice rather than compulsory adherence. This nuanced and democratic approach ensures that while the sanctity of national symbols is preserved, individual rights are not unduly compromised-a balance that sets India apart from the strict regulatory models seen in Russia and parts of Europe, where legal conformity is enforced with little tolerance for dissent. ■

(Author is Associate professor, School of Law Governance and public policy, Chanakya University, Bengaluru)

सुधी पाठकों!

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मई 2025 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakt I. In
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.x.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

मुद्दों पर मंथन, समाधान की चर्चा

सर्वस्पर्शी, समावेशी एवं सशक्त भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं युवा

■ अजीत कुमार सिंह

एक दशक बाद राजधानी दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जनजातीय छात्र संसद, छात्रा संसद एवं पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में युवाओं ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन विचार-विमर्श करके देश को पूर्ण विकसित बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सामने रखा। तीन दिवसीय छात्र संसद केवल विमर्श या चर्चा करने भर का मंच नहीं रहा, बल्कि देश के विविध क्षेत्रों से आए छात्रों-युवाओं के लिए यह अत्यंत परिवर्तनकारी कदम सिद्ध हुआ।

छात्र संसद में आए प्रतिनिधियों ने न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, पूर्वोत्तर भारत के विकास सहित सांस्कृतिक विविधताओं के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, बल्कि इसके समाधान की दिशा में विस्तृत योजना भी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साझा की। बांग्लादेशी घुसपैठ पर नियंत्रण, उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, आधारभूत संरचना का विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी और युवाओं के लिए विशेष औद्योगिक नीति जैसी कई दूरगामी नीतिगत मांगों के साथ ही विकास के प्रति छात्र मुखर दिखाई दिए।

देश के शैक्षिक एवं राजनीतिक मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने के लिए लालायित छात्रों-युवाओं के विचारों को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए छात्र संसद का आयोजन करके अभाविप ने न केवल अपने दायित्व का निर्वहन किया, बल्कि राजधानी दिल्ली में सुदूर ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र से लेकर उत्तर-पूर्व के युवाओं को एक मंच देकर उन्हें अपनी समस्याओं को संबंधित नीति-नियंताओं के साथ साझा करने का महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान किया। तीन दिवसीय छात्र संसद का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गत 09-11 मार्च को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) सभागार में किया। दस वर्ष बाद अभाविप द्वारा आयोजित छात्र संसद से यह भी सिद्ध हुआ कि उचित मंच मिलने पर सभी मिलकर देश के समग्र विकास के महत्वाकांक्षी अभियान में जुट सकते हैं।

आज देश में चरित्र निर्माण की बात करने वाला यदि कोई छात्र संगठन है, तो वह केवल अभाविप है। पूर्वोत्तर के छात्रों को अभाविप से जुड़ना चाहिए। साथ ही पूर्वोत्तर छात्र संगठनों के बीच सेतु बनने का कार्य भी अभाविप को करना चाहिए।

***अमित शाह**, केंद्रीय गृहमंत्री*

जनजातीय समाज केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का वाहक है। भारतीय संस्कृति अरण्य प्रधान संस्कृति रही है और जनजातीय समाज आज भी इस सनातन परंपरा का संवाहक बना हुआ है।

***दुर्गादास उइके**, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री*

अभाविप ने पूरे पूर्वोत्तर को देश की राजधानी में एक मंच पर लाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छात्र और युवा भारत का भविष्य हैं और इस भविष्य को मजबूत और सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्वोत्तर अपार क्षमता, धन और शक्ति से भरा क्षेत्र भारत की 'अष्ट लक्ष्मी' है। अगर पूर्वोत्तर मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा।

***सर्बानंद सोनोवाल**, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री*

अभाविप एक ऐसा छात्र संगठन है, जिससे छात्रों को प्रबंधन एवं नेतृत्व निर्माण सीखने को मिलता है। भविष्य में इस संगठन से अनेकों महिला नेतृत्वकर्ता तैयार होंगी। छात्रा संसद के माध्यम से अभाविप एक विचार रूपी वटवृक्ष तैयार कर रही है, जिसकी छांव में राष्ट्र निर्माण की नींव रखी जाएगी।

***रेखा गुप्ता**, मुख्यमंत्री, दिल्ली*

छात्र संसद के पहले दिन अखिल भारतीय जनजातीय छात्र संसद में जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति एवं अवसर, जनजातीय समाज का वर्तमान परिदृश्य और जनजातीय समाज की संस्कृति-परंपरा का सशक्तिकरण में हमारी भूमिका विषय पर चार प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही स्वाभिमान और देश की विकास यात्रा में जनजातीय समाज की भूमिका तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर पांच सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रभाव एवं उन्हें बेहतर बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

76 से अधिक जनजातीय समुदाय के 271 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आयोजित जनजातीय छात्र संसद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र से पूर्व प्रास्ताविक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक ने जनजातीय समाज के स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति-परंपरा एवं विकास पर विस्तार से चर्चा की। जनजातीय छात्र कार्य प्रमुख प्रमोद राउत ने कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए छात्र संसद के महत्व को सामने रखा। विशिष्ट अतिथि के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. आशुतोष मांडवी ने अभाविप द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अभाविप जनजातीय छात्रों के मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास के साथ अपनी संस्कृति-परंपरा को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है।

छात्र संसद के दूसरे दिन 10 मार्च को आयोजित छात्रा संसद में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन जैसे विषयों पर गहन मंथन हुआ। छात्रा संसद में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों को बढ़ावा देना, कौशल पर काम करना, खेती एवं सब्जी आदि उत्पादन में रोजगार की अपार संभावनाओं पर बल दिया गया। चर्चा में सहभाग करते हुए विभिन्न प्रांत की छात्राओं ने अपने क्षेत्र के मुद्दे सदन में रखे।

चर्चा के दौरान स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन करना, रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं के कौशल को प्राथमिकता देना, ऋण आदि की प्रक्रिया को सरल करना आदि जैसे विषय भी सामने आए।

विभिन्न प्रांत की छात्राओं ने अपने क्षेत्र के मुद्दे सदन में रखे। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु जागरूकता बढ़ाना, सेमेस्टर सिस्टम में सुधार, छात्राओं हेतु सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल आधारित पाठ्यक्रम में सुधार, छात्रावासों में बढ़ोतरी करना, पौष्टिक आहार जागरूकता, शैक्षणिक संस्थाओं में सैनिटरी वेंडिंग मशीन की उपलब्धता बढाना, स्वास्थ्य केंद्रों को तहसील स्तर तक बढ़ाना, छात्राओं में योग एवं व्यायाम की जागरूकता बढ़ाना, शैक्षणिक संस्थाओं में महिला चिकित्सक की नियुक्ति होना आदि जैसे विषयों पर चर्चा के बाद संभावित समाधान के ड्राफ्ट भी बनाए गए।

चर्चा के आधार पर अभाविप ने एक मांग पत्र भी बनाया, जिसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को सौंपा गया। तीन सौ से अधिक छात्रा प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित छात्रा संसद में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे, सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा के साथ ही अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी, अखिल भारतीय छात्रा कार्य प्रमुख मनु शर्मा कटारिया, राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा, दिल्ली प्रांत अध्यक्ष तपन बिहारी सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। छात्रा संसद में देश की 316 छात्रा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

छात्र संसद के अंतिम दिन 11 मार्च को आयोजित 'पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद' में युवाओं ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। युवाओं ने एक स्वर में कहा कि हम सभी यहां उत्तर-पूर्व भारत के विकास पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, ताकि 2047 तक आत्मनिर्भर उत्तर-पूर्व और विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में एक ओर जहां उग्रवाद, सीमा सुरक्षा, नशाखोरी, भौगोलिक कठिनाईयों पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर आपसी मतभेद को दूर रख हुए पूर्वोत्तर के विकास के लिए 95 से अधिक छात्र संगठनों के प्रतिनिधि एकमत दिखे। सभी ने विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं भविष्य की राह की रूपरेखा पर भी चर्चा की।

पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में एक ओर जहां उग्रवाद, सीमा सुरक्षा, नशाखोरी, भौगोलिक कठिनाईयों पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर आपसी मतभेद को दूर रखते हुए पूर्वोत्तर के विकास के लिए 95 से अधिक छात्र संगठनों के प्रतिनिधि एकमत दिखे।

पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन, पूर्वोत्तर के पारंपरिक कौशल को संरक्षित एवं संवर्धित करने जैसे विषयों पर चिंतन-मनन कर समाधान पर चर्चा करके सरकार के प्रतिनिधि को भी अवगत कराया गया।

अभाविप प्रकल्प अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) के तत्वावधान में आयोजित पूर्वोत्तर छात्र युवा संसद में पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों से 95 छात्र संगठनों के 170 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही अभाविप के पूर्वोत्तर राज्यों के 50 प्रतिनिधि और दिल्ली में कार्यरत विभिन्न पूर्वोत्तर छात्र संगठनों के 50 प्रतिनिधियों ने भी संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मुकुंद सी. आर., केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, सील के ट्रस्टी सुनील वासुमतारी, राष्ट्रीय मंत्री कमलेश सिंह, अभाविप अरुणाचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री कु. बिकी यादर सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। तीन दिवसीय छात्र संसद में विचार किए गए विषयों, मुद्दों एवं आगामी कार्ययोजना को लेकर बनी सहमति आगामी समय में अभाविप के लिए वरदान सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ■

ज्ञान, शील एवं एकता से होगा राष्ट्र का पुनर्निर्माण : डा. मोहन भागवत

देश की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रकल्प अंतर राज्य जीवन दर्शन (सील) के कार्यालय की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। कार्यालय का नाम 'यशवंत' रखा गया है, जिसका निर्माण यशवंतराव जी के जन्म शती वर्ष में किया गया। जिस प्रकार सील प्रकल्प को यशवंतराव जी ने आगे बढ़ाया था, उसी भावना से अभाविप का यह कार्यालय बना है, जिसमें 'ज्ञान, शील और एकता' का मूल भाव निहित है। विद्यार्थी परिषद को समझना हो तो उसके कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, क्योंकि घटक पूर्ण मिलकर सम्पूर्णता का निर्माण करते हैं। यह सन्देश रा.स्व.संघ के सरसंघचालक डा. मोहनराव भागवत ने यशवंत भवन के लोकार्पण अवसर पर देश के विद्यार्थियों को दिया।

दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित यशवंत नामक नए भवन के लोकार्पण के बाद भवन परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करके संघ प्रमुख डा. भागवत ने कार्यालय भवन का अवलोकन भी किया। गत 22 अप्रैल को यशवंत भवन के लोकार्पण समारोह में सरसंघचालक डा. मोहनराव भागवत ने कहा कि अभाविप कार्यकर्ताओं के अनुभवों से गढ़ी गई है, संघ पर संकट के समय भी राष्ट्रीय विचार के आधार पर कार्य करते हुए, परिषद ने अपने आकार को पाया है। कार्यालय केवल एक भवन नहीं, कार्य का आलय होना चाहिए, क्योंकि जैसा कार्य होगा, वैसी ही परिषद बनेगी। संगठन में आत्मा और बुद्धि के साथ शरीर भी आवश्यक है, अधिक तामझाम की आवश्यकता नहीं, अपितु मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आज हमारे देश और विश्व में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में हमें ऐसा देश बनाना है, जिसमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती हो। यह सामर्थ्य तरुणों में है और उन्हें केवल दिशा और ज्ञान की आवश्यकता है। यह ज्ञान भी तभी सार्थक है जब उसमें एकता हो। विविधता को सम्मान देते हुए भी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को अपनाना है। एकता के बिना शील नहीं होता, और शील के बिना ज्ञान शक्ति प्रदर्शन का साधन बन जाता है, जैसा हम इतिहास और वर्तमान दोनों में देखते हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का बड़ा योगदान होता है। उत्साह में हम भूल जाते हैं जो नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के भाग्य में कुछ-कुछ

परिवर्तन आ रहा है और विश्व में भी कुछ-कुछ परिवर्तन दिख रहा है। दुनिया लड़खड़ा रही है और वह भारत की ओर देख रही है। उन्होंने सभी रास्तों पर चलकर देख लिया लेकिन समाधान नहीं मिला। अब एक ही आशा है भारतवर्ष से और भारतवर्ष की पीढ़ी के मन में भी बात जागी है कि अपने देश को अच्छा और सुंदर देश बनाएंगे।

इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. राजशरण शाही ने कहा कि अभाविप के अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) कार्यालय का लोकार्पण उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सहभागिता और तप से संभव हुआ है, जिन्होंने इस स्वप्न को साकार करने के लिए अपना योगदान दिया। यह कार्यालय प्रा. यशवंतराव के नाम पर समर्पित है, जिन्होंने कार्यकर्ता और विद्यार्थी जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इस कार्यालय का आकार आज हमारे सामने खड़ा है। यह कार्यालय न केवल अभाविप के संगठनात्मक कार्यों का सशक्त केंद्र बनेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका को भी नई दिशा देगा।

अभाविप संगठन के निर्माण में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के तप और आहुति को प्रणाम करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि नए भवन के निर्माण से उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। वर्तमान समय में उत्तर-पूर्वी राज्यों में दो लाख से अधिक अभाविप कार्यकर्ता बहु-रचनात्मक कार्य में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्रों का केंद्र अब यशवंत भवन बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

जानकारी हो कि प्राध्यापक यशवंतराव केलकर एक प्रखर विचारक, कुशल संगठक और प्रख्यात शिक्षाविद् थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में रचनात्मकता, राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना के बीजारोपण का जो कार्य प्रारंभ किया, वह आज अभाविप के विशाल संगठनात्मक स्वरूप में प्रतिफलित हो रहा है।

सील प्रकल्प की स्थापना 1966 में पूर्वोत्तर भारत एवं शेष भारत के बीच आपसी संवाद, स्नेह और सांस्कृतिक एकात्मता को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से हुई थी। यह प्रकल्प आज हजारों युवाओं को देश की विविधता को समझने और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को सशक्त बनाने हेतु प्रेरित कर रहा है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित यशवंत भवन का निर्माण ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रख कर इस तरह किया गया है कि प्राकृतिक प्रकाश और वायु का अधिकतम प्रवेश संभव हो सके। यह आधुनिक भवन निर्माण के सभी मानकों पर खरा उतरता है। परिसर में एक खुले रंगमंच स्थान का निर्माण भी किया गया है, जहां विविध गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। नौ तल वाले भवन में दो भूमिगत तल, एक भूतल तथा छह ऊपरी तल हैं।

भवन में डेढ़ सौ से अधिक लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक सभागार, बहुउद्देश्यीय सभागार, शोधार्थियों के लिए सुसज्जित पुस्तकालय तथा पूर्वोतर के विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां से वह अपनी अकादमिक गतिविधियों का संचालन कर सकेगें। परिसर में एक सुंदर उद्यान भी विकसित किया गया है, जो इसे एक जीवंत, हरित और प्रेरणादायी वातावरण प्रदान करता है। परिसर में स्वामी विवेकानंद की 12 फीट ऊंची अष्टधातु की भव्य प्रतिमा तथा सभागार के बाहर संगमरमर पर उत्कीर्ण सरस्वती माता की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो परिसर को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करती हैं। ■

भारत की स्वतंत्रता सेनानी रानी अबक्का

■ मंदार भानुशे

सामान्यतः इतिहास की पुस्तकों में यह बताया गया है कि भारत देश का इतिहास पराजय एवं गुलामी का इतिहास रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि देश का इतिहास हमेशा से पराक्रम, शौर्य और बलिदान का रहा है। भारत माता वीर प्रसूता भूमि है। आक्रांता अनेकों आए, पर कभी भी चैन से राज्य नहीं कर पाए। सैंकड़ों-हजारों स्वतंत्रता सेनानी, योद्धा, जिनमें से कईयों के नाम आज के युवा जानते भी नहीं है, ऐसे पराक्रमी लोगों ने अपनी मातृभूमि को बाह्य आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए पुरजोर प्रयास किए। वीरांगना रानी अबक्का की शौर्य गाथा भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के रूप देखी जा सकती है। इस वर्ष उनकी जन्मजयंती का 500वां वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 500वीं जन्मजयंती को मना रहा है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से रानी अबक्का कौन थी? कहां से थी? उनका पराक्रम क्या था? इतिहास में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? और उनको स्मरण क्यों करना चाहिए? जैसी कई जिज्ञासा, उत्सुकता से भरे प्रश्न सभी के मन में है। रानी अबक्का की शौर्य गाथा की जानकारी देश को गर्व के साथ होनी चाहिए।

वीरांगना रानी अबक्का चौटा कर्नाटक प्रदेश के तटीय क्षेत्र 'तुलुनाडु' की रानी थी। उन्हें उल्लाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। सोलहवीं सदी की पराक्रमी रानी अबक्का को अभया रानी भी कहा गया क्योंकि वह कभी किसी से डरती नहीं थी। निडर, प्रजाहित के लिए समर्पित, व्यापार और युद्ध दोनों में प्रवीण, रानी अबक्का ने लगभग चार दशकों तक पुर्तगाली सेना पर बार-बार विजय प्राप्त करने और उनके हमलों को कुचलने का कार्य बड़ी चतुरता तथा शौर्य से किया।

रानी अबक्का चौटा, उल्लाल की पहली तुलुवा रानी थीं। वह दिगम्बर पंथी जैन चौटा राजघराने में जन्मीं थी, जो कि मातृवंशीय परंपरा को मानने वाले थे। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जहां निर्णय प्रक्रिया में स्त्रियों को परिवार में प्रमुख माना जाता है और शासन-संपत्ति में उनको अधिकार दिया जाता है। रानी अबक्का के पूर्वज गुजरात के जैन राजवंशी थे, जो संभवतः बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में आकर बस गए थे। रानी अबक्का के मामा राजा तिरुमाला राय ने उन्हें 1544 में उल्लाल की रानी बना दिया।

तत्कालीन समय में तुलुनाडु क्षेत्र की राजधानी पुत्तिगे थी और उल्लाल एक प्रसिद्ध व्यापारी बंदरगाह नगर था। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को-दा-गामा के भारत आने के बाद तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने व्यापार के नाम पर अपना कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारतीय राजाओं को डरा-धमकाकर उनसे एकाधिकारपूर्ण अनुबंध कराने के अलावा अरब और फारस के साथ उनके व्यापारिक संबंध तोड़ने का प्रयास किया। कुछ ही समय में पुर्तगालियों ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से लेकर केरल के कालीकट

तक अपना कब्जा जमा लिया। अपनी सैन्य ताकत के जोर पर पुर्तगाली समुद्री मार्ग से होने वाले सभी तरह के व्यापार पर कप्पा अर्थात कर वसूलने लगे। कई राजा पुर्तगालियों के दबाव में झुक गए, लेकिन कुछ ने प्रतिरोध किया। इसमें प्रमुख रूप से कालीकट के जमोरिन और उल्लाल की रानी अबक्का थी।

1525 में जन्म लेने वाली अबक्का को छोटी उम्र से ही एक अच्छा शासक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अबक्का एक असाधारण बालिका थीं। उन्हें तलवार चलाना, सैन्य रणनीति, तीरंदाजी, घुडसवारी, कूटनीति, राजनीति और राज्य चलाने के लिए आवश्यक अन्य विषयों की शिक्षा दी गई थी। युद्ध में तीर-कमान में अग्निबाण का उपयोग करने वाली वह शायद आखिरी भारतीय योद्धा थीं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। जब वह सभी क्षेत्रों में पारंगत हो गई, तो उनका विवाह मंगलुरु की बंगा रियासत के राजा लक्षमप्पा अरसा से कर दिया गया। यह विवाह लम्बे समय तक नहीं चला और फिर पति से रिश्ते खराब होने के बाद वह वापस उल्लाल आ गईं। इसी कारण लक्षमप्पा ने अबक्का के विरुद्ध बदला लेने की योजना बनाई और 1570 में अबक्का से लड़ने के लिए पुर्तगालियों के साथ एक संधि में शामिल हो गया।

पुर्तगालियों ने उल्लाल को जीतने का अनेक बार प्रयत्न किया, पर रानी अबक्का ने उनकी हर कोशिश साहस और चतुराई से नाकाम कर दी। इतिहास की पुस्तकों में दुर्भाग्य से रानी गुमनाम कर दी गई, पर कई पीढ़ियों से कर्नाटक के लोकगीतों और लोककथाओं में रानी अबक्का की शौर्य गाथा को बताया जाता है। 'यक्षगान' और 'भूतकोला' जैसी लोकप्रथाओं में रानी का गुणगान आज भी होता है। रानी अबक्का सभी प्रजाजनों के साथ समानता का व्यवहार करती थी। यही कारण था कि राज्य के सभी जाति एवं पंथ के लोग न केवल उनका आदर करते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते थे। रानी अबक्का की सेना में सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व था। स्थानीय मछुआरा समाज "मोगावीरा" भी उनकी सेना में सम्मिलित था। न्यायप्रिय एवं प्रजा के हित का विचार- यह उनके कार्य की विशेषता रही है। उल्लाल में पानी की समस्या न हो, इसलिए उन्होंने उस समय नौ तालाब बनवाए थे, जो आज भी जल की आपूर्ति की दृष्टि से उपयुक्त हैं। यह उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यकुशलता का परिचायक कहा जा सकता है।

पुर्तगालियों ने 1555-56 में रानी अबक्का के विरुद्ध एडमिरल डॉन अल्वारो दा सिल्वरेरा को भेजा, लेकिन रानी अबक्का की बहादुरी के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पुर्तगालियों ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।

भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित उल्लाल किसी समय एक उपजाऊ एवं व्यापारिक क्षेत्र होने के अलावा मसालों और वस्त्रों के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। रानी अबक्का के नेतृत्व में यह राज्य प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करने के पश्चात मंगलुरु की तटीय रेखा पर कई बंदरगाह स्थापित कर लिए, जिसके बाद उनका ध्यान उल्लाल पर गया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण उल्लाल पुर्तगालियों का अगला लक्ष्य बना। पुर्तगालियों ने रानी अबक्का से कर वसूलने के लिए उन्हें डराने-धमकाने के लिए कई प्रयास किए, जो विफल रहे। पुर्तगालियों ने 1555-56 में रानी अबक्का के विरुद्ध एडमिरल डॉन अल्वारो दा सिल्वरेरा को भेजा। एडमिरल सिल्वरेरा के हमले को रानी अबक्का ने बहादुरी के साथ असफल कर दिया। इसके बाद कई बार पुर्तगालियों ने रानी अबक्का पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।

1567-68 में पुर्तगाली वाइसराय एंटनी डी नोरोन्हा ने अपने सेनापति को बेड़े के साथ उल्लाल पर कब्ज़ा करने के लिए भेजा। इस बार वह उल्लाल के शाही मैदान में घुस गया। रानी अबक्का, हमेशा की तरह दृढनिश्चयी और तैयार थी। इसलिए वह बच निकली। लेकिन उसी रात उल्लाल जीतने की खुशी मना रही पुर्तगाली सेना पर रानी अबक्का ने अपने दो सौ योद्धाओं के साथ हमला किया और फिर पुर्तगाली जनरल एवं उसके सत्तर सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद रानी अबक्का अपने उल्लाल को पुनः प्राप्त करने में कामयाब हुई।

रानी अबक्का पुर्तगाली सेना की ताकत से भलीभांति परिचित थीं। इसलिए उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को युद्धकला में प्रशिक्षित किया। घास काटने के औजार को ही रस्सी बांध कर लड़ाई में उसका शस्त्र बनाकर उपयोग करना, उन्होंने ही महिलाओं को सिखाया। साथ ही अपने राज्य की सभी महिलाओं को दुश्मनों से लड़ने के लिए तलवारों से युद्ध का अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्होंने 'पोन्नुले पाडे' नाम से अपने सैन्यदल में एक महिला दल का गठन भी किया था।

पुर्तगाली सेना ने 1569 में मंगलूर किले और कुंदापुर पर कब्ज़ा कर लिया। रानी अबक्का पुर्तगालियों के लिए अब बड़ा खतरा बन गई थीं। कूटनीति में कुशल रानी अबक्का ने अहमदनगर के बीजापुर सुल्तान और कालीकट के ज़मोरिन के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पुर्तगाली एडमिरल को मार दिया और पुर्तगालियों के कब्जे से मंगलूर किले को मुक्त करा लिया।

1570 में रानी के साथी और कालीकट के जमोरिन की सेना के जनरल कुट्टी पोकर जब मंगलूर से वापस जा रहे थे, तब पुर्तगालियों ने उनको छल से मार दिया। इसके बाद पुर्तगाली पुनः उल्लाल को हासिल करने के प्रयास करने लगे। अपने राज्य को किसी भी हालत में विदेशी आक्रान्ताओं का गुलाम न बनने का दृढनिश्चय लेने वाली रानी अबक्का, दुर्भाग्य से 1570 में पुर्तगालियों के साथ हुई अंतिम लड़ाई में हार गई। 1525 से 1570 तक सात बार पुर्तगालियों ने उल्लाल को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पुर्तगालियों ने रानी अबक्का को कैद कर लिया। लेकिन वह जेल के अंदर भी अकेले विद्रोह का नेतृत्व करने में अडिग रहीं और अंततः उस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गई। अपने अदम्य साहस के लिए आज भी रानी अबक्का को याद किया जाता है। 2009 में भारतीय नौसेना के एक तटरक्षक जहाज को रानी अबक्का का नाम देकर उनके कार्य को सम्मानित करने का सराहनीय प्रयास हुआ। 2003 में उनकी स्मृति में भारतीय डाक ने एक डाक टिकट जारी किया। कर्नाटक में 'वीर रानी अबक्का प्रशस्ति' पुरस्कार महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। उल्लाल तथा बेंगलुरू में उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके बाद भी देशवासियों को रानी अबक्का के बारे कोई विशेष जानकारी नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि रानी अबक्का जैसी वीरांगनाओं के पराक्रम और कार्यों को आगामी पीढ़ियों को बताने के लिए आगे आना चाहिए। ■

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)

। निर्णय ।

एफटीआईआई और एसआरएफटीआई को मिला मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

केंद्र सरकार ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टिट्यूट आफ इंडिया (एफटीआईआई) एवं कोलकाता स्थित सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टिट्यूट (एसआरएफटीआई) को मानद विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटी) का दर्जा दे दिया है। इस निर्णय के बाद दोनों संस्थान डिग्री और शोध शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एक्ट-1956 की धारा-3 के अंतर्गत दिया गया है। अब यह संस्थान शोध शिक्षा के साथ ही नवोन्मेषी प्रोग्राम भी आरंभ कर सकेंगे। दोनों संस्थानों को यूजीसी के नियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही दोनों संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स से भी जोड़ा जाएगा। जानकारी हो कि पुणे में एफटीआईआई की स्थापना 1960 में प्रभात स्टूडियो में हुई थी। पहले इसका नाम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, जिसे 1971 में बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसी तरह कोलकाता में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना 1995 में हुई और इसका नाम विख्यात फिल्मकर सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

DIPEX-2025
Showcases Innovation and Youth Talent Across Maharashtra and Goa

The 34th edition of DIPEX-2025, a prestigious state-level exhibition-cum-competition showcasing working models by students from Diploma, Degree, Post-Graduate Engineering, Agriculture, and ITI programs across Maharashtra and Goa, was successfully held from 3rd to 6th April 2025 at the CoEP Ground, Pune. Organised jointly by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) and SRIJAN Trust, the event witnessed enthusiastic participation and vibrant innovation. CoEP Technological University, Ministry of Skill Development of Maharashtra, Savitribai Phule Pune University, along with institutions such as Maharashtra Natural Gas Limited (MNGL), Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, TATA BlueScope Steel India Limited, AICTE, DTE Maharashtra, MSBTE, and the Maharashtra State Innovation Society were the co-organisers and supporters of the event.

DIPEX-2025 revolved around critical technological themes such as Agricultural Technology, Computational Intelligence, Defence and Cyber Security, Energy, Industrial Automation, Medical and Healthcare Technology, Mobility, Sustainable Civil Infrastructures, Safety, Waste Management, and Open Innovation.

For the first time in its history, DIPEX introduced Idea Presentation Rounds across 11 regional centres throughout Maharashtra and Goa to expand outreach and participation. These rounds were held in Solapur, Ahilyanagar, Pune, Kolhapur, Karad, Nagpur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Nanded, Jalgaon, Mumbai, and Ratnagiri, drawing nearly 1,300 teams and over 5,500 students from more than 400 institutions. The rigorous evaluation, conducted by more than 350 experts, led to the final selection of 324 projects, including 301 from engineering colleges (150 diploma and 175 degree projects) and 83 from ITIs across 28 districts, totalling around 1,412 participants.

DIPEX-2025 began on 3rd April with a flag hoisting ceremony led by Dr. Shantinath Bagewadi and Atharva Kulkarni of ABVP, followed by the inauguration of the Late Ratan Tata Pradarshani by dignitaries including

and chaired by Sanjay Inamdar, reinforcing the importance of youth leadership in national development.

The evening featured the landmark program "Vision Maharashtra 2047," with an inspiring address by Chief Minister Devendra Fadnavis alongside other ministers and key stakeholders, underlining the state's future roadmap through youth empowerment, innovation, and sustainability. On the concluding day, 6th April, a seminar on "Academic Research for Societal and Industrial Impact" brought together academic and industry leaders such as Dr. Rahul Walavalkar, Dr. Avinash Kulkarni, Dr. Sunil Bhirud, and Santosh Gurav, chaired by Vikas Patil, offering valuable guidance to mentors and faculty on translating academic work into real-world solutions.

Dr. Sanjiv Sonawane, Dr. Sharad Goswami and Aditya Muske. The grand inaugural ceremony in the evening was graced by eminent personalities such as Dr. G. Satheesh Reddy, Minister Chandrakant Dada Patil, Ashish Chouhan, Dr. Sunil Bhirud and others who inspired the gathering with their insights and encouragement. On 4th April, the event featured a seminar on "Opportunities in the Defence Sector" by Kashinath Deodhar and a panel discussion on "The Future of Impact-Driven Startups" moderated by Kanak Kawadiwale with contributions from Sheetal Arjunwadkar, Pradeep Peshkar and Girish Degaonkar.

An interactive session with Padmashree Milind Kamble recounted his journey from DIPEX to DICCI, offering an inspiring narrative for young entrepreneurs. The third day, 5th April, hosted a panel on "AI Powered Future of Bharat" featuring experts like Ramanand Nand, Rishi Bal, Dr. Amit Dutta and Kailash Katkar, moderated by Dr. Sarita Balshetwar. Concurrently, ITI students attended a motivational Marathi seminar, "मी उद्योजक होणारच," by Prof. Vijay Navale. The day also included a session titled "Vision 2047 and Youth of Bharat" delivered by Sudhir Mutalik

This was followed by the project evaluation by over 110 subject matter experts. The evening culminated with a grand valedictory and prize distribution ceremony attended by eminent dignitaries including Prof. T. G. Sitharam (AICTE), Dr. Virendra Singh Solanki (ABVP), Ram Bhogale (SRIJAN Trust), Dr. Suresh Gosavi (SPPU), and others who honoured the innovators and highlighted the importance of such platforms in nurturing technical talent. The presence of leaders like Uday Samant, Pankaj Bhoyar, and Prakash Javadekar added further prestige to the ceremony. DIPEX-2025 concluded with a strong commitment to promoting innovation and empowering the next generation of technocrats and entrepreneurs for a developed and self-reliant Bharat. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

प्राध्यापक कार्यकर्ता वर्ग का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गुजरात प्रांत द्वारा दो दिवसीय प्राध्यापक कार्यकर्ता वर्ग का आयोजन किया गया। वर्ग में अभाविप गुजरात के अलग-अलग लगभग 16 विभागों से विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर के दायित्ववान प्राध्यापक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अभाविप की कार्यप्रणाली, कार्य कुशलता और परिसर कार्यकर्ता के साथ कार्य करने की कार्यपद्धति को समझा।

गुजरात के जूनागढ़ में गत 18 एवं 19 मई को संपन्न वर्ग का शुभारंभ माता सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रास्ताविक एवं वर्तमान समय में अभाविप की प्रासंगिकता विषय पर अभाविप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. सुरभिबहन दवे एवं राष्ट्रीय सह संगठनमंत्री देवदत्त जोशी ने चर्चा की। वर्ग में हुए विभिन्न सत्रों में गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री हिमालय सिंह झाला ने अखिल भारतीय विचार बैठक विषय पर, मूल विचार विषय पर अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने, प्राध्यापक कार्यकर्ता की भूमिका विषय पर अभाविप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. मंदार भानुशे ने, शिक्षा में बदलाव एवं अमलीकरण विषय पर राष्ट्रीय विशेष आमंत्रित सदस्य डा. छगनभाई पटेल ने, संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए बैठक, संपर्क और प्रवास विषय पर अभाविप पश्चिम क्षेत्रीय संगठन मंत्री गीतेश चव्हाण ने विस्तार से चर्चा की। वर्ग के दौरान विद्यार्थी निधि न्यास सदस्य प्रा. शेखर चंद्रात्रे ने आदर्श प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में जिज्ञासा, समाधान एवं समारोप सत्र के साथ प्राध्यापक कार्यकर्ता वर्ग संपन्न हुआ। वर्ग में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह संगठनमंत्री देवदत्त जोशी एवं अभाविप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मणभाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

श्रीमद्भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र 'विश्व स्मृति रजिस्टर' में शामिल

प्राचीन सनातन धार्मिक ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता और भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसी के साथ विश्व स्मृति रजिस्टर में पंजीकृत संग्रहों की कुल संख्या 570 हो गई है। यह रजिस्टर पुस्तकों, पांडुलिपियों, मानचित्रों, फोटो, ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी प्रलेखित विरासत की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यवान अभिलेखागार और पुस्तकालय संग्रह संरक्षित एवं सुलभ हों।

यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजूले के अनुसार एक स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा प्रविष्टियों के मूल्यांकन और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अन्तिम निर्णय के बाद श्रीमद्भगवद्गीता और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को उनके सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है। जानकारी हो कि 18 अध्यायों वाली श्रीमद्भगवद्गीता एक पवित्र संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ में महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद के माध्यम से आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इसी तरह 36 हज़ार श्लोकों से युक्त भरतमुनि का नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर आधारित प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, है, जो नाटक, प्रदर्शन, सौंदर्य अनुभव, भावना और संगीत को परिभाषित करता है। नाट्यशास्त्र में दी गई रस (सौंदर्य अनुभव) की अवधारणा, भारतीय कला और संस्कृति की नींव रही है।

श्रीमद्भगवद्गीता और भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र को शामिल किए जाने के बाद विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारत के संग्रहों की संख्या चौदह हो गई है, जिनमें ऋग्वेद, शैव पांडुलिपियां और तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह जैसी अहम विरासत शामिल हैं। विश्व स्मृति रजिस्टर का आरंभ 1992 में हुआ था और इसका उद्देश्य मानवता की लिखित या दर्ज विरासत के संरक्षण और सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

लेह में बना विश्व का पहला 3डी-प्रिंटेड बंकर

विश्व का पहला 3डी-प्रिंटेड सैन्य बंकर लेह में बनाया गया है। सैनिकों के लिए तैयार किया गया यह बंकर ग्यारह हजार फिट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण सेना की सिम्पलीफोर्ज क्रिएशंस एवं हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने संयुक्त रूप से किया है। जानकारी के अनुसार लेह में 3डी-प्रिंटिंग तकनीक से बने बंकर का निर्माण प्रोजेक्ट प्रबल के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट प्रबल दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक सैन्य बंकर बनाने का एक अभियान है। 3डी-प्रिंटिंग तकनीक वह तकनीकी है, जो पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी ढंग से निर्माण कार्य करती है। 3डी-प्रिंटेड बंकर को बनाने में आईआईटी (हैदराबाद) टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम ने एक रोबोटिक प्रिंटर सिस्टम बनाया, जिसे स्थापित करने में 24 घंटे से भी कम समय लगा और प्रिंट करने में 14 घंटे लगे। इस संरचना का निर्माण स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों से किया गया था, जो प्रतिकूल मौसम के लिए स्थिरता और अनुकूलन सुनिश्चित करता है। 3डी-बंकर निर्माण की यह उपलब्धि भविष्य में सेना को दुर्गम क्षेत्र में उन्नत सुरक्षात्मक संरचनाएं बनाने में मदद करेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

छात्र संसद

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं अभाविप पदाधिकारी

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद में उपस्थित पूर्वोत्तर छात्र संगठनों के प्रतिनिधि, अभाविप पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथि

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 MAY, 2025
DATE OF PUBLISHING: 8 MAY, 2025

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवनिर्मित कार्यालय 'यशवंत'